





# शेयर बाजार तेजी साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुंबई शेयर बाजार मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन पिछले पांच कारोबारी की संख्या भी ऊपर आया। वही बीएसई सेसेक्स और अपर आया। बाजार और बीएसई और सेसेक्स के साथ एक साथ दूसरी और एक कारोबारी दिन आया। वही ट्राईप्लाई बैंक और एचडीएप्लाई बैंक, एचडीएप्लाई लि. और आरआरएल एक के शेयर में आई तेजी के साथ ही यूरोपीय बाजारों से मिले अच्छे सेक्टों से आई है। इन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधिकारी बीएसई सेसेक्स 366.64 अंक के बाक 0.4 अंक बंद हुआ। निर्दिती 50 के गीर्ह 5 कंपनियों में एक्सिस बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक के शेयर गहरी वही इंडेक्सेज की बात करते ही पीएसयू बैंक में 4 फीसदी से भी ज्यादा तेजी आई। इसके बाद ऑटो क्लियर 2 फीसदी के शेयरों में सबसे ज्यादा कीरीब सात एकिक के शेयर मिले।

**बैंकों के शेयर भागे**  
निर्दिती भी 2.05 फीसदी की बढ़त हासिल की ही थे 75.9.20 अंकों की बढ़ोत्तरी के साथ 10.0 पर बंद हुआ। निर्दिती 50 के गीर्ह 5 कंपनियों में एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएप्लाई बैंक के शेयर गहरी वही इंडेक्सेज की बात करते ही पीएसयू बैंक में 4 फीसदी से भी ज्यादा तेजी आई। इसके बाद ऑटो क्लियर 2 फीसदी के शेयरों में सबसे ज्यादा कीरीब सात एकिक के शेयर मिले।

**एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। एल्युमीनियम उद्योग ने मोटी सरकार से एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की है। भारतीय एल्युमीनियम संघ (एएआई) ने पर्याप्त धरेल एल्युमीनियम कबाड़ की खात पर 100 एल्युमीनियम आयात पर निर्भर है। इसका कारण एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।" एल्युमीनियम और एल्युमीनियम कबाड़ पर मूल सीमा शुल्क अन्य अलोहा धूतों जैसे जस्ता, सीमा, निकेल और टिन के अनुरूप नहीं है। यह धरेल एल्युमीनियम उत्पादकों के लिए एक

बड़ा नुकसान है। उद्योग को इसके अलावा मूल सीमा शुल्क की दर या अधिकतम सीमा शुल्क दर मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की उम्मीद है। उद्योग के अनुसार, एल्युमीनियम कबाड़ के बढ़ते आयात से प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग को अंधीरा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कुल आयात में एल्युमीनियम कबाड़ की उपलब्धि विवादी विवादी 2015-16 में 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। अब धरेल एल्युमीनियम कबाड़ की उपलब्धि विवादी विवादी 2020-22 में 66 प्रतिशत हो गई। इसके कारण 15,000 कोरोड़ रुपये के बराबर की खपत लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। प्राथमिक एल्युमीनियम पर वर्तमान 7.5 फीसदी, डाउनट्रॉफ एल्युमीनियम पर 7.5 से 10 प्रतिशत और एल्युमीनियम क्लैप पर 40 सिफे 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क है।

**टीपीसीआई ने खाद्य तथा पेय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आम बजट को लेकर सुझाव दिए**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय नियंत्रित संबंधित परिषद (टीपीसीआई) ने खाद्य तथा पेय उद्योग के बढ़ावा देने के मकान से मोटी सरकार को बढ़ते में देश में बने उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणाएं करने का सुझाव दिया।

परिषद ने साथ ही एसेंजेड (विशेष अंधिक क्षेत्र) इकाइयों को कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का भी सुझाव दिया है। टीपीसीआई ने उद्योग के लिए इनपुट टैक्स क्रॉसिंग की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर मोटी सरकार के मकान से एक अंतर सरकारी निकाय है। वर्ष 2016 में स्थापित, कोडेक्स एलिमेंट्रियस की रक्षा के लिए संयुक्त खाद्य और पेय स्थापित करने की खपत लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। प्राथमिक एल्युमीनियम पर वर्तमान 7.5 फीसदी, डाउनट्रॉफ एल्युमीनियम पर 7.5 से 10 प्रतिशत और एल्युमीनियम क्लैप पर 40 सिफे 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क है।

**सेबी ने इंसजी रेटिंग एजेंसियों के नियमन के लिए रूपरेखा प्रस्ताव पेश किया**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। बाजार नियामक सेबी ने पर्यावणा, सामाजिक एवं कामकाज के संचालन (ईएसजी) से संबंधित रेटिंग देने वाली फर्मों के नियमन के लिए सेवा विकास को लेकर 2.5 प्रतिशत करने की खपत लगभग पूरी तरह से अधिक मूल्य वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं विश्लेषक फर्मों ही ईएसजी रेटिंग सेवा प्रदाता (ईआरपी) के तौर पर योग्यता दिया गया है।

**2030 तक लगभग 18 गीगाबार्ट पनाबिजली क्षमता बढ़ाने की जरूरत**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। गीगाबार्ट पनाबिजली क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी। केंद्र नियमन के लिए एसजीएस को लेकर कारोबारी की तुलना में अधिक है और पुनरुद्धार पूरे देश में हुआ है। भारतीय अंधव्यवस्था में निष्पक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

**अंदरूनी अब धारी के अल-जफरा वायर सेवा को हो जाएगी।**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। गीगाबार्ट पनाबिजली क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी। केंद्र नियमन के लिए एसजीएस को लेकर कारोबारी की तुलना में अधिक है और पुनरुद्धार पूरे देश में हुआ है। भारतीय अंधव्यवस्था में निष्पक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

**2030 तक लगभग 18 गीगाबार्ट पनाबिजली क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी।**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। गीगाबार्ट पनाबिजली क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी। केंद्र नियमन के लिए एसजीएस को लेकर कारोबारी की तुलना में अधिक है और पुनरुद्धार पूरे देश में हुआ है। भारतीय अंधव्यवस्था में निष्पक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को लेकर बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

**महामारी के व्यवधानों से काफी हृद तक उबर चक्की है भारतीय अर्थव्यवस्था**  
नई दिल्ली (ईएमएस)। नीति आयोग के पूर्व उपायकारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित महामारी के बचाने के लिए ग्रेनेजहन की खाद्य और खाद्य की धोणी की इकाइयों पर अधिकारी ने बाजार के लिए उत्पादों के प्रयाप्त-प्रसार और विपणन जैसी गतिविधियों के साथ आधिकारिक अनुरूपान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ग्रेनेजहन की धोणी की इकाइयों को

